

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

: आयुक्त (अपील -I) का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, :  
: सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, :  
: आंबावाडी, अहमदाबाद- 380015. :

क फाइल संख्या : File No : V2(21)47 /Ahd-III/2015-16/Appeal-I

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-041-16-17

दिनांक Date : 11.07.2016 जारी करने की तारीख Date of Issue \_\_\_\_\_

श्री अभय कुमार श्रीवास्तव आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित

Passed by Shri Abhai Kumar Srivastav Commissioner(Appeals-I)Ahmedabad

ग \_\_\_\_\_ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I आयुक्तालय द्वारा जारी मूल  
आदेश सं \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_ से सृजित

Arising out of Order-in-Original: AHM-CEX-003-DC-09-2015 Date: 29.05.2015  
Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Kalol, A'bad-III.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Food Solution India Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे  
बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as  
the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

**Revision application to Government of India :**

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में  
पूवोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार,  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को  
की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision  
Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building,  
Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the  
following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने  
में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में  
चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a  
warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of  
processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क  
कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित  
है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside  
India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any  
country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया  
माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of  
duty.



ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- षोबी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

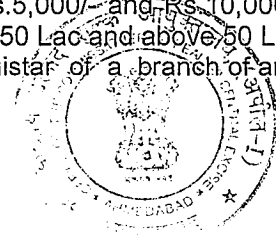
(a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

(ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

(b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 39फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1998 की धारा 43 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

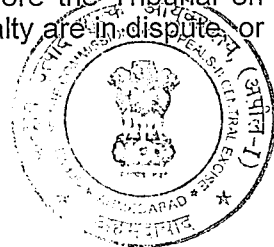
Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



**ORDER-IN-APPEAL**

M/s Food Solutions (I) Ltd, situated at Shed No.1, Silver Estate, Nr. Akshar Gravures, Rakanpur, Tal-Kalol (hereinafter referred to the appellant) filed an appeal against the Order-in-Original No.AHM-CEX-003-DC-09-2015 dated 29.05.2015 (hereinafter referred to as "the impugned order) passed by the Deputy Commissioner of Central Excise, Kalol Division, Ahmedabad-III (hereinafter referred to as "the adjudicating authority")

2. The appellant is engaged in the manufacture of Soups, Sauces, Gravies etc falling under Chapter 21 of Central Excise Tariff Act, 1985 and is registered with the the Central Excise Department. The appellant's factory premise was searched by the Central Excise Officers on 06.03.2014, on the basis of information that the appellant had indulged in gross negligence to the obligations cast upon them under Central Excise procedures. On scrutiny of records, it was observed that the appellant had not maintained their daily stock register as per provisions of Rule 10 of Central Excise Rules, 2002; that the daily stock register was maintained / available only for the period of six days, i.e, from 01.03.2014 to 06.03.2014 and all the entries were written with pencil, except the first one indicating opening balance. During verification of goods lying in stock as on 06.03.2014, the officers also found variation when compared to stock recorded in the daily stock register. As the finished goods did not match even with the daily stock register written with pencil and the appellant could not given any explanation for such variation and also for not maintaining records of production, clearance, etc. prior to 01.03.2014, the entire stock of finished goods valued at Rs.24,55,702/- lying at the factory premises was seized on the reasonable belief that the same was intended to be cleared without payment of duty. A Show Cause Notice dated 22.05.2014, proposing confiscation of seized goods and imposition of penalty under Rule 25 of Central Excise Rules, 2002 was issued. This SCN was adjudicated vide impugned order, wherein the seized goods were ordered for confiscation with an option to redeem on payment of fine of Rs. 6,13, 926/-. Further, a penalty of Rs. 50, 587/- was imposed on the appellant.

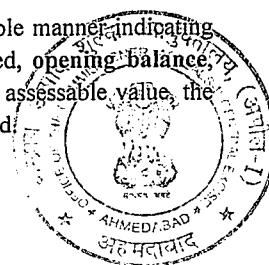
3. Being aggrieved, the appellant has filed the present appeal on the grounds that the seizure of entire physical stock was not tenable; that there was no evidence of any clandestine removal or indication of to *malafide* on the part of appellant; that improper accountal of goods and shortage of finished goods found during stock taking was due to shortage of staff and inadequate infrastructure; that only the differential quantity noticed during stock taking should be treated as unaccounted and possibly liable for confiscation; and that in view thereof, fine and penalty ought to have been token.

4. Personal hearing in the matter was held on 16.06.2016 and Shri Nilesh Bhatt appeared before me, on behalf of the appellant. He reiterated the averments made in their written submissions dated 24.06.2015 and requested for leniency.

5. I have carefully gone through the facts of the case narrated in the appeal and other relevant documents. The case pertains to confiscation of seized goods, found not properly accounted; and consequent imposition of redemption fine and penalty.

6. Rule 10 of Central Excise Rules, 2002, *inter alia*, stipulates that:

1) Every assessee shall maintain proper records, on a daily basis, in a legible manner, indicating the particulars regarding description of the goods produced or manufactured, opening balance, quantity produced or manufactured, inventory of goods, quantity removed, assessable value, the amount of duty payable and particulars regarding amount of duty actually paid.



(2) ....

(3) All such records shall be preserved for a period of five years immediately after the financial year to which such records pertain.

In view thereof, the appellant, a registered manufacturer, was under legal obligation to maintain proper records of production, mentioning opening balance, quantity manufactured, inventory of goods, quantity removed etc, on a day-to-day basis, duty payable on removal and duty actually paid. Further, the appellant was required to preserve records of last five years. In the instant case, the Central Excise officers, on visit to the factory of the appellant on 06.03.2014, noticed that the appellant had not maintained the requisite records for the period prior to 01.03.2014 indicating the said particulars, as prescribed under Rule 10 *ibid*. The daily stock register was available for only six days' period (01.03.2014 to 06.03.2014), and that too was maintained casually in pencil, except the first entry of opening balance. Previous records for the period 10.09.2013 to 28.02.2014 were not maintained, as admitted by the assessee, who had taken registration on 10.09. 2013.

7. I observe that: (i) despite getting registered with Central Excise Department in September 2013, the assessee accepted having not maintained any records of production, opening balance, clearance etc. , as mandated in rule 10 *ibid*, for the period Sept 2013 to 28.02.2014; (ii) they did not file any return for that period, for which a separate SCN stands issued; (iii) in the absence of any "recorded closing balance" as on 28.02.2014, there is no sanctity of an "opening balance" mentioned on a daily stock register for 01.03.2014; and therefore all the other entries mentioned in pencil thereafter also lose their sanctity as their veracity cannot be crosschecked.

8. It would be pertinent to look at the relevant excerpts from Rule 25 of the CER 2002:

**RULE 25. Confiscation and penalty.** — (1) Subject to the provisions of section 11AC of the Act, if any producer, manufacturer, ..... -

(a) removes any excisable goods in contravention of any of the provisions of these rules or the notifications issued under these rules; or

(b) does not account for any excisable goods produced or manufactured or stored by him; or

(c) .....

(d) contravenes any of the provisions of these rules or the notifications issued under these rules with intent to evade payment of duty,

then, all such goods shall be liable to confiscation .....

9. The difference between two independent provisions 25(1)(b) and 25(1)(d) *ibid* needs to be highlighted. Any excisable goods, if not accounted for, are liable to confiscation and the intent to evade duty is not a necessary prerequisite for the same. Therefore, in view of findings at Para 7 above, stock of all excisable goods on 06.03.2014 was liable for confiscation, in consonance with the provisions enumerated in rule 25(1)(b) of the Central Excise Rules, 2002. The appellant has cited shortage of staff and inadequate infrastructure for their failure to maintain proper records, as required under the law. This reason for contravening the law is not tenable. Non maintenance of records for the period from the date of registration to 01.03.2014 and recording entries in a casual manner with pencil after 01.03.2014 clearly indicates lack of *bonafide* on the part of the appellant. The assessee also contravened the rules by not filing excise returns.

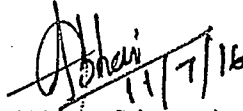


these contraventions and omissions need to be seen in the context of the sensitive nature of commodity, gravies and soups, due to their easy saleability in open market and restaurants, which are not institutional buyers. These facts compel me to hold that the provisions of Rule 25(1)(d) *ibid* also are attracted independently, to hold confiscation. Therefore, I find no reason to interfere with the impugned order with regard to order of confiscation of seized goods and quantum of redemption fine.

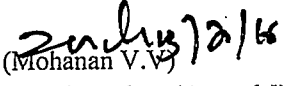
10. Further, failure to maintain accounts of goods manufactured and cleared by the appellant attracts penalty under the provisions of Rule 25 of Central Excise Rules, 2002 which stipulates a penalty not exceeding the duty on the excisable goods in respect of which such contravention has been committed, or rupees two thousand, whichever is greater. Looking into the facts of the case, blatant disregard for the legal obligations regarding maintaining accounts of production, inventory and clearance, absence of records for 2013-14, sensitive and evasion prone nature of the seized goods, I find no reason to interfere with the quantum of penalty imposed.

11. In view of above discussions, I reject the appeal filed by the appellant and uphold the impugned order.

Date: 11/07/2016

  
(Abhai Kumar Srivastav)  
Commissioner (Appeals-I)  
Central Excise, Ahmedabad

Attested

  
(Mohanan V.V.)  
Superintendent (Appeal-I)  
Central Excise, Ahmedabad

BY R.P.A.D

To

M/s Food Solutions (I) Ltd.  
situated at Shed No.1, Silver Estate  
Nr. Akshar Gravures, Rakanpur, Tal-Kalol  
Gandhinagar, Gujarat

Copy to:

1. The Chief Commissioner, Central Excise Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-III
3. The Addl./Joint Commissioner, (Systems), Central Excise, Ahmedabad-III
4. The Dy. / Asstt. Commissioner, Central Excise, Division- Kalol, Ahmedabad-III
5. Guard file.
6. P.A.

